दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बारी से पहले मकानों तथा दुकानों का आवंटन

17. **डा० अबरार अहमद :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए संसद सदस्य मकान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रावधान हैं, और यदि नहीं, तो सरकार संसद सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से मकान दिलवाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या मंत्री महोदय को दिल्ली में मकान अथवा दुकान आबंटित करने के लिए कोई वैवेकिक शक्तियां अथवा कोटा प्राप्त है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा पिछले 15 महीनों के दौरान इस प्रकार आबंटित मकानों तथा दुकानों की संख्या कितनी है एवं उनके आबंटितियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली के उपराज्यपाल को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों अथवा दुकानों को बारी से पहले आबंटित करने की कोई वैवेकिक शक्तियां अथवा कोटा प्राप्त है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार आबंटित किए गए मकानों की संख्या सहित उनके आबंटितियों के नाम क्या-क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान/फ्लैट के आवंटन के लिए स्वयं को पंजीकृत करा सके और न ही ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/दुकान आबंटित करने के लिए शहरी विकास मंत्री का कोई वैवेकिक कोटा नहीं है।

(ग) उपराज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण अति अनुकम्पा तथा विपत्ति के मामलों में तथा विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को और ऐसे अन्य विशेष मामलों में जो कि उनकी राय में विशेष ध्यान दिये जाने के पात्र हैं जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाया है तथा जिनको राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, रक्षा कार्मिक जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए शौर्य पुरस्कार जीते हैं, और राष्ट्रीय जीवन धाराओं के अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के मामलों में एक वर्ष के दौरान आबंटित फ्लटों की कुल संख्या का 2% आबटन बिना बारी आधार पर करने में सक्षम है।

उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर आबंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का विवरण संलग्न है। (देखिये परिशिष्ट 159, अनुपत्र सं० 2)

राजस्थान में जिला मुख्यालयों को रेलवे से जोड़ा जाना

18. **डा० अबरार अहमद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या-क्या हैं जो रेलवे से जुड़े हुए नहीं हैं और इनके कब तक रेलवे से जोड़े जाने की संभावना है;

(ख) क्या कोटा से दिल्ली तक एक नई गाड़ी चलाने की कोई योजना है;

(ग) क्या कोटा-बीना रेलवे लाइन पर कोई एक्सप्रेस (द्रुत गति) गाड़ी चलती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रेलव लाइन पर पिछले कितने वर्षों से कोई नई एक्सप्रेस (द्रुत गति) गाड़ी नहीं चलाई गई है; और